चूंकी माननीय मंत्री जी हमारे प्रदेश से संबंध रखते हैं इसलिए तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हू कि जो यू. पी.एफ़. और डी. पी. एफ़. है, जिनके माध्यम से हम सड़क नही बना पा रहे है, क्या उसके लिये माननीय मन्त्री जी ने कोई योजना बना रखी है?

श्री शांता कुमार : सभापति जी, हिमाचल प्रदेश में 2000-2001 में साठ करोड़ रूपए दिए गए थे इसमें से 59.31 करोड़ रूपये खर्च हुए, 2001-2002 में एक सौ छियत्तर करोड़ रूपये दिए थे, इसमें से 46 करोड़ रूपये खर्च हुए । यह एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया हैं किसी प्रदेश में जितने गांव अनकनेक्टेड होते हैं, उनमें से प्रतिवर्ष कुछ गांव लिए जाते हैं। इन्हें पूरा किया जाएगा। किसी प्रदेश में कितनी सड़कें किस साल में ली गई, टोटल कितने धन का प्रावधान किया गया, कितना खर्च किया गया, इसकी सूचना प्रत्येक सांसद और प्रत्येक विधायक को भेज रहे हैं ।

श्री सभापति : ये सूचना आप अभी दे दीजिए।

श्री अनिल शर्मा : सभापति जी, मेरा सैकिण्ड सप्लीमेंट्री हैं ।

श्री सभापति : इसमें स्टेट का क्वेशचन है। इन्होंने जवाब दे दिया है, आप उसे देख लीजिए।

अपराध करने के पश्चात् विदेश भागने वाले अपराधी

*208. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'** : ††

लाला लाजपत राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षो के दौरान अनेकों लोग भारत में अपराध करके विदेश भाए गए हैं ,

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और ये किस-किस देश में छिपें हैं,

(ग) क्या सरकार ने इन लोगों को वापस भारत में लाकर न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए विदेशों में वहां की सरकारों से सम्पर्क किया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किस-किस देश से सम्पर्क किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई.डी.स्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया ।

(क) से (घ) भारत द्वारा वांछित 166 भारतीय अपराधियो के अन्य देशों में छिपे होने की सम्भवना हैं।

भारत सरकार ने उनके प्रत्यार्पण के लिए निम्नलिखित सरकारो से सम्पर्क किया है:-

(i) संयुक्त अरब अमिरात

(ii) पुर्तगाल

(iii) अमेरिका

(iv) इग्लैंड

(v) फ्रांस

(vi) मलेशिया

(vii) कनाडा

(viii) जर्मनी

इसके अलावा, पाकिस्तान सरकार से भी सम्पर्क स्थापित किया गया था और उन्हें 31 दिसम्बर, 2001 को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए फरार हुए 20 व्यक्तियों की एक सूची, विभिन्न न्यायालयों में उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें भारत को सौंपने के अनुरोध के साथ दी गई थी ।

Criminals escaping abroad after committing crime

†*208. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN' :††

SHRI LAJPAT RAI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of people after committing crimes in India during the last three years have escaped abroad;

(b) if so, the total number thereof and the countries they are hiding in;

†Orlginai notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

(c) whether Government have contacted the Governments of those countries for their extradition and for trying them in the court; and

(d) if so, the countries which have been contacted in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): (a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) 166 Indian criminals wanted by India are likely to be hiding in other countries.

The Government of India have contacted the following Governments fortheir extradition:—

(i) United Arab Emirates

(ii) Portugal

(iii) United States of America

(iv) United Kingdom

(v) France

(vi) Malaysia

(vii) Canada

(viii) Germany

In addition, Government of Pakistan was also contacted and given a list of 20 fugitives of law on 31st Dec, 2001 with the request to hand them over to India for trial in different Courts of law.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति जी, सरकार ने उत्तर में बताया है कि एक सौ छियासठ भारतीय अपराधी हैं जो यहां अपराध करने के बाद विदेशों में शरण लिए हुए हैं । सरकार ने बीस फरवरी को अतारांकित प्रश्न संख्या एक सौ बियासी के उत्तर में बताया है कि अब तक मात्र तीन अपराधी प्रत्यर्पण के माध्यम से देश मे लाए गए हैं। सभापति जी, ये जो एक सौ छियासठ अपराधी हैं इनमें कई तरह के अपराधी हैं । कई अपराधी ऐसे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुम्बई बम काण्ड जैसे बड़े अपराद्यों में अपराधी हैं। कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो **…(व्यवधान)…**

श्री सभापति : आप क्यों क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं । आप अपराधियों के संबंध मे पूछ लीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : वही पूछ रहे हैं ।

श्री सभापति : वही पूछ लीजिए

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : कई अपराधी ऐसे हैं जो बोफोर्स जैसे मामले में दलाली करके विदेश में शरण लिए हुए हैं। यह सूचना भी है कि इन लोगों को राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है । सी.बी.आई. ने भागने का मौका दिया **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : मैं यह अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री सुरेश पचौरी : तहलका वाले अपराधी भी हैं। उन्हें भी बता दीजिए **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : ठहरिए, ठहरिए **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : बोफोर्स वाले साबित हो चुके हैं । हमने आपका नाम तो नहीं लिया है **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : मैं अलाऊ नहीं करूंगा । आप स्ट्रेट क्वेश्चन कर लीजिए ।अपराधी की डेफिनेशन और क्वालीफिकेशन बताने की आवश्यकता नहीं है । **...(व्यवधान)..** मैं यह अलाऊ नहीं करूंगा । **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या क्वात्रोची को भगाने में सी.बी.आई. के अधिकारियों ने मदद की थी? उन्हें यहां लाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है?

श्री सभापति : यह आपका क्वेश्चन नहीं है।

श्री राजीव रंजन सिहं 'ललन' : क्वेश्चन नहीं है ।

श्री सभापति : आपका क्वेश्चन अपराधियों का हैं। आप हर अपराधी के लिए पूछेंगे कि यह अपराधी इटली गया था उसका क्या हुआ।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति जी, मैं तो पूछ रहा हूं । क्वात्रोची अपराधी हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सभापति जी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में क्वात्रोजी का नाम भी हैं, दाउद का नाम भी है और भी बहुत से नाम हैं । जिन-जिन कंट्रीज में वे हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं हैं। तकरीबन नौ कंट्रीज के साथ हमने संपर्क साधा है। उसमें पाकिस्तान को, जो 20 दाऊद जैसे लोग हैं, उनके लिए भी कहा गया है और उसके लिए कोशिश हो रही है । लेकिन उसकी प्रक्रिया जरा लंबी है। हमने उन कंट्रीज से काटैक्ट जरूर किया है।

श्री सभापति : उनको पकड़ने में माननीय सदस्य का सहयोग ले लीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, इस पूरी कार्यवाही में कितने दिन का समय लगेगा ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : इसके बारे में कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती ।

लाला लाजपत राय : चेयरमैंन सर, जो जवाब दिया गया है उसमे यह कहा है कि पाकिस्तान के अदंर 20 अपर धी हैं और उनके बारे में 31 दिसंबर, 2001 को कुछ बात-चीत की गई। आज उसको एक साल दो महीने हो गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बीच में क्या कार्यवाही की गई ? नंबर दो ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : नंबर दो नहीं, आप एक ही कर लीजिए ।

लाला लाजपत राय : थोड़ा सा है ।

श्री सभापति : नहीं ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, कांस्टैट रेव्यू में ऐसी चीज रहती है, जैसे हाउस के आनरेबल मैबर्स अच्छी तरह से अवगत हैं कि जब कभी भी पाकिस्तान से डिप्लोमैंटिक लेवल पर कोई बात हुई है या वे लोग यहां आए हैं या कहीं भी हमारी बात हुई हैं तो उस वक्त इसको प्रैस किया गया है कि बीस की जो लिस्ट दी गई हैं उन अपराधियों को हमारे सुपुर्द किया जाए। यही सरकार कर सकती है और इसके लिए प्रक्रिया जारी है ।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, I want to know whether, as reported, the Government of Portugal have agreed to extradite Mr. Abu Salem immediately. How many other criminals are there in Portugal who are wanted by our security agencies?

THE DEPUTY PRIME MINISTER, IN CHARGE OFTHE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, the Portugese Government has said that 'we are willing to hand him over under our laws.' So, tie crime for which he has been first detained, that process has to be completed, and then action is taken in respect of deportation.

SHRI EDUARDO FALEIRO: My question is: How many other criminals are there in Portugal?

SHRI L.K. ADVANI: They have also suggested that we formally write to them about deportation, and we have written to them.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, I had asked as to how many other criminals are there in Portugal who are wanted by us.

SHRI L.K. ADVANI: No, that we are not aware of.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, I want to know from the hon. Minister whether the Ministry of Home Affairs is getting enough cooperation from the Ministry of External Affairs in getting these criminals extradited.

SHRI I.D. SWAMI: Yes; Sir, always, all Ministries are extending all cooperation. And, the Ministry of Home Affairs is certainly getting the cooperation of the Ministry of External Affairs.

Computerisaton of land records

*209. SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to accelerate the process of digitization and computerization of land records in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the new computerization programme would help the farmers to establish land ownership, to record succession of ownership and to maintain crop details and obtain bank loans?

THE MINISTER FOR RURAL DEVELOPMENT (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (c) The main objective of the Centrally Sponsored Scheme of Computerisation of Land Records is to provide computerised copies of ownership, tenancy and crop details as also copies of digitised cadastral survey maps to the landowners/tenants on demands.The computerised copies of Records of Rights can be used by farmers for borrowing money from financial institutions.

The implementation of the Scheme is being reviewed regularly by the Ministry of Rural Development to accelerate me process of digitisation and computerisation of land records in the country through conferences of Revenue Ministers/Secretaries of the States and Union Territories, video conferencing, Area Officers visits and Quarterly Progress Reports (QPRs). So far 582 districts and 2970 tehsils/taluks/blocks of the country have been covered and the Ministry have released Rs. 263.51 crores to States/Union Territories under this Scheme.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, my first supplementary is this. You also know, Sir, that the implementation of the present ceiling laws is extremely tardy, and it is all the more unfortunate that lately an environment is being sought to be created for providing exemption from ceiling laws to the industry and big farmers. Some State Governments have already gone ahead with giving relaxation without seeking the permission of the Government of India. I would like to know whether the Government is in favour of such an exemption. If not, what concrete measures have been